



तपस पहल

 drishtiias.com/hindi/printpdf/tapas-initiative

पिरलिम्स के लिये:

तपस पहल, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान

मेन्स के लिये:

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहलें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने एक ऑनलाइन पोर्टल '**उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण**' (Training for Augmenting Productivity and Services- TAPAS) लॉन्च किया है।

TAPAS के विचार की अवधारणा ऐसे समय में की गई थी जब कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण कार्य करने और शिक्षा के लिये ऑनलाइन माध्यम की खोज करना अनिवार्य हो गया था।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिये सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (NISD)** की एक पहल है।
सामाजिक सुरक्षा को प्रायः राज्य और नागरिक समाज दोनों द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के रूप में समझा जाता है।
- यह एक मानक **मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC)** प्लेटफॉर्म है जिसमें फिल्माए गए व्याख्यान और ई-अध्ययन सामग्री जैसी पाठ्यक्रम सामग्री होती है।
MOOC एक मुफ्त **वेब-आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम** है जिसे बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें छात्रों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच बातचीत और प्रोत्साहित करने के लिये चर्चा मंच भी शामिल है।
- यह अध्ययन सामग्री के आधार पर विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान तक पहुँच प्रदान करेगा, इस प्रकार यह शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किये बिना भौतिक कक्षा के पूरक का काम करता है।
- जो भी अपने विभिन्न विषयों पर ज्ञान को बढ़ाना चाहता है उसे प्रयोग कर सकता है और इसमें शामिल होने के लिये कोई शुल्क नहीं है।

- मंच को निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है:
वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट और चर्चाएँ।

कोर्सज:

पाँच बुनियादी कोर्स जैसे- नशीली दवाओं (पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम, जरा चिकित्सा/बुजुर्गों की देखभाल, मनोविकृति की देखभाल एवं प्रबंधन, ट्रांसजेंडर और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

उद्देश्य :

इसका मुख्य उद्देश्य **प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना** है।

महत्त्व :

- हमारी शिक्षा प्रणाली में जहाँ अध्यापन की ऑफलाइन विधा की पैठ काफी गहरी है, उसके लिये यह पाठ्यक्रम परिवर्तन सुनिश्चित करने के साथ ही **नई संभावनाओं के लिये मार्ग प्रशस्त** करेगा।
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से **सामाजिक सुरक्षा के साथ सीखने और काम करने** में बड़ी संख्या में लोगों को सक्षम बनाएगा।

अन्य डिजिटल लर्निंग पहल:

- **स्वयं (SWAYAM) :**
ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिये एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई, 2017 को स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) लॉन्च किया गया था।
- **स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha) :**
 - यह 24X7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (Direct to Home- DTH) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।
 - इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है।
- **प्रौद्योगिकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT) :**
इस योजना का उद्देश्य **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)** की सहायता से सीखने वाले की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप एक अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना है।
- **प्रौद्योगिकी वर्द्धन शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPTEL) :**
NPTEL भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरु के साथ सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) द्वारा शुरू की गई MHRD की एक परियोजना है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (NISD)

परिचय:

- NISD एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT), दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है।

- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हेतु एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है। यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है।
- यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। यह राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार व गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय तथा संपर्क का कार्य भी करता है।

केंद्र:

संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।

शासनादेश:

संस्थान का अधिदेश प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों हेतु जानकारी प्रदान करना है।

स्रोत: पीआईबी
